*302 [The questioner (Shrimati Prema Carippa and Prof Alka Balram Kshatriya) were absent. For answer *vide* page 52]

Construction of dwellings under IAY in Punjab

*303. SHRI VARINDER SINGH BAJWA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of dwellings constructed in Punjab under Indira Awaas Yo1a during 2004-05 against the target fixed; and

(b) the dwelling units likely to be constructed during 2005-06?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Against the target of 7408 houses, 4460 houses have been constructed under the Indira Awaas Yojana (IAY) during the year 2004-05 in the State of Punjab.

(b) During 2005-06, 11081 houses are likely to be constructed under the IAY

SHRI VARINDER SINGH BAJWA: Sir, I would like to know from the hon. Minister, through you, as to what measures they take into consideration while allocating funds to a State under the Indira Awaas Yojana.

श्री सभापति: आपने प्रश्न नहीं सुना । सुन तो लिया न। क्वैश्चन सुन लिया?

श्री रघुनंश प्रसाद सिंह: जी नहीं ।

श्री सभापति: आप एक बार फिर से प्रश्न बोल दीजिए।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: आप इंन्दिरा आवास योदना में किस ढंग से ये फंड्स स्टेट्स को एलोकेट करते हैं, इसके क्या फैक्टर्स हैं?

श्री सभापति: फंड्स कैसे एलॉट किए जाते हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हाउसिंग शॉर्टिज पर 75 परसेंट वेटेज हैं और 25 परसेंट वेटेज शैडयूल्ड कास्ट्स शैडयुल्ड ट्राइब्स के पॉपुलेशन पर दिया गया है। उसी आधार पर हर जिले में फंड का एलाटमेंट होता है।

श्री सभापति: आपका सेंकड सप्लीमेटरी है? नहीं है। श्री राजीव शुक्ल।

श्री राजीव शुक्ल: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

हुं कि उनके जवाब में है कि पंजाब को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 7 हज़ार का जो लक्ष्य दिया गया था, उससे कम घर उन्होंने बनाए हैं, इसी तरह उड़ीसा ने अपने बजट का सिर्फ 54 प्रतिशत खर्च किया. तो ऐसे राज्य, जिन्हें आप जो बजट देते हैं, वे उसका पूरा उपयोग नहीं करते और बहुत कम खर्च करते हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि कई जगह अनियमितताओं की शिकायतें आई है।

श्री सभापति: नहीं, दुसरा सवाल नहीं। आप एक ही का जवाब दीजिए।

श्री राजीव शुक्ल: उनका सवाल ही पूछ रहा हूं । कई जगह इरेंगुलेरिटीज़ की शिकायत हैं कि अंडर बीपीएल...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह छोड़िए, पहले इस क्वैश्चन का जवाब आने दीजिए।

श्री राजीव शुक्ल: जो लोग बिलों पोवर्टी लाइन नहीं है, उन्हें भी यह दिया जा रहा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, इन्दिरा आवास योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट केन्द्र सरकार का हिस्सा 75 प्रतिशत होता है और राज्य सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत होता है। दोंनों राशि को मिला कर इन्दिरा आवास योजना के घर बनाए जाते हैं । इसमें कुछ राज्य सरकार कभी-कभी अपना स्टेट शेयर समय पर रिलीज नहीं करती और कभी-कभी करती ही नहीं, इस कारण जो लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति नहो होती।

महोदय, दुसरी बात यह है कि इसमें भी जो राशि उपलब्ध है, कोई-कोई जिला उसको भी किसी कठिनाई से खर्च नहीं कर पाते। इसके लिए हम यहां से लिखा-पढ़ी करते है, हमारे अधिकारी अधिकारी स्तर पर लिखा-पढ़ी करते हैं, फिर हम चीफ मिनिस्टर से लिखा-पढ़ी करते हैं। जब हमने यह तय किया है कि जिस जिले में खर्च समय पर नहीं होगा, उस जिले के डीआरडीए एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो वेतन देते हैं, उस वेतन पर भी रोक लगाने पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन पहले हम राज्य सरकार को मुख्यमंत्री स्तर पर इस वास्ते आगाह करते हैं।

श्री मुख्तार आब्बास नकवी: आदरणीय सभापति, महोदय, इन्दिरा आवास योदना के तहत केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारों के सहयोग से जो योजना चलाती है, उसमें बड़े पैमाने पर अनियामितताएं और कहीं-न-कहीं घपले-घोटाले सामने आते रहे हैं. माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर एक निगरानी समिति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वास्तविक रूप से वह घोषणा सिर्फ घोषणा है। उस घोषणा को माननीय मंत्री जी जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं उतार पाए है। मेरा प्रश्न यह है कि इन्दिरा आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार जो 75 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकारों को देती है, तो प्रदेश सरकारें उसका उपयोग नहीं कर पाती है या दुरूपयोग करती है, इसके लिए किसी निगरानी की व्यवस्था केन्द्र सरकार की है?

श्री रघूवंश प्रसाद सिंहः सभापति महोदय. डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनीटरिंग कमेटी तमाम ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए है और इस में माननीय सदस्य भी को-चैयरमेन है।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : नहीं है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सभापति जी, मैंने स्वयं गांवों में देखा है कि इन्दिरा आवास योजना के मकान ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है पानी की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार को आप यह सलाह देंगे कि इंदिरा आवास योजना के मकान जो बनाए रहे हैं। उन की क्वालिटी ठीक हो, उन में सुविधाएं पूरी हों और वहां रहने वालों की सुरक्षा की व्यवस्था हो। क्या इन तीन बातों का निर्देश आप उन्हें देंगे ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हम बराबर सुझाव देते रहते हैं और भी देंगें।

डा.कुमकुं राय: महोदय. इंदिरा आवास योजना जो कार्यन्वित की जा रही है, उस के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिलाकर 25 हज़ार रुपए प्रतियूनिट दिया जाता है। महोदय, इस मंहगाई के जमाने में 25 हज़ार रुपए में क्या बन सकता है? इसलिए मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इस राशि को और बढ़ाए जाने के बारे में आप सोच रहे हैं?

श्री सभापति: यह क्वैश्चन नहीं बनता, आप बैठ जाइए। अगला प्रशन 304.

SEZs established in the **country**

*304. SHRI SHAHID SIDDIQUI: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the State-wise details of SEZs established so far;

(b) what are the advantages of establishing the SEZs; and

(c) how many of these SEZs have been established in backward regions of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI E.V.K.S. ELANGOVAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.